

सार समाचार

मॉब अटैक: मरी भैंस ले जा रहे युवकों को घसीट-घसीटकर पौटा, पुलिस ने बचाई जान

हाथरस (एजेंसी)। राजस्थान में गाय रक्षकों द्वारा किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत पर भारी प्रतिक्रिया के बीच बुधवार तड़के उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भीड़ ने एक मृत भैंस को ले जा रहे चार लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि, इस बार गनीमत यह रही कि पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर चारों युवकों की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार, हाथरस जिले में एक मृत भैंस को ले जा रहे चार कथित पशु तस्करों को भीड़ ने बुधवार तड़के पहले तो पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर हाथरस जिले के नगला मांधाता गांव की है। बताया जा रहा है कि भैंस चोरी के आरोपी इन लोगों को पुलिस कर्मियों ने उग्र भीड़ से बड़ी मुश्किल से बचाया। पुलिस कर्मी करीब आधा घंटे तक भीड़ से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील करते रहे तब जाकर भीड़ ने उन्हें पुलिस के हवाले किया। गांव वालों का आरोप है कि तस्कर पिकअप वैन से मृत भैंस को लेकर जा रहे थे और उन्होंने भैंस को जहर देकर मारा था। वहीं, भैंस मालिक का भी आरोप है कि पशु तस्करों ने उसकी भैंस को जहर का इंजेक्शन दिया था। हसायन थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार ने बताया जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भीड़ के हाथों पिटाई का शिकार हो रहे कथित तस्करों को किसी तरह बचाया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है अगर गिरफ्तार किए गए चारों लोग पशु तस्कर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सामूहिक मुंडन: शिक्षामित्रों ने बाल मुंडवाकर किया प्रदर्शन

लखनऊ (एजेंसी)। आम शिक्षक/ शिक्षामित्र एसोसिएशन के बैनर तले नियुक्ति की मांग को लेकर इकोगार्डन, आलमबाग में 69 दिन से धरना दे रहे शिक्षामित्र बुधवार को एक बार फिर उग्र हो गए। लगातार सरकार की उदासीनता से खफा एसोसिएशन की अध्यक्ष उमा देवी समेत दो दर्जन से अधिक पुरुष व महिला शिक्षामित्रों ने सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर अचेत रह रही है। शहीद हुए शिक्षामित्रों के लिए प्रदेश भर के शिक्षामित्रों ने श्रद्धांजलि दी। इसमें दूसरे पहर तपन, श्राद्ध किया। हाथों में तिरंगा लिए हक की मांग को लेकर शिक्षामित्र धरना स्थल से बाहर इकोगार्डन गेट पहुंच गए। नारेबाजी करके विरोध जताया। कहा कि महिलाओं के अपमान के बाद भी सरकार नहीं मानती है। तो करो या मरो की नीति अपनाई जाएगी। गेट पर पहुंचे एसोसिएम तुलसी ब्रजेन्द्र कुमार ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोष दुबे का कहना है कि सरकार नहीं चेती तो विरोध-प्रदर्शन तेज होगा।
मांग:-
1-आरटीई एक्ट 2009 के तहत पूर्ण शिक्षक का दर्जा और वेतनमान
2- उत्तराखण्ड के अनुसार टेट उतीर्ण करने की छूट मिले।
3-जो टेट उतीर्ण है उन्हें बिना लिखित परीक्षा उम्मी और अनुभव का भारों पर नियमित किया जाय।
4- असमायोजित शिक्षामित्रों को समान कार्य-समान वेतन दिया जाए।
5- मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता व एक सदस्य को योग्यता के मुताबिक नौकरी मिले।

यूपी: प्राइमरी स्कूलों के नाम से हटाया जाएगा 'इस्लामिया' शब्द, अब रविवार को ही होगी छुट्टी

बलिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बलिया जिले के इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय अब सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के नाम से ही जाने जाएंगे। इन विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश भी शुक्रवार के बजाय अन्य सभी प्राथमिक विद्यालयों की तरह रविवार को ही होगा। इस्लामिया प्राथमिक विद्यालयों पर लिखे 'इस्लामिया' शब्द को हटाने और शुक्रवार को अवकाश के मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा क्षेत्र सीयर में खण्ड शिक्षा अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने बुधवार को बताया कि शिक्षा क्षेत्र सीयर में कुल छह इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय हैं। ये विद्यालय उधवा, कुण्डेल, बासगार, बहोरावा, अनांव, तिनई और पिपरीली बड़गांव में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में रविवार के बजाय शुक्रवार को ही अवकाश होता रहा है।



मंगलवार को भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट के दल ने भेंट की।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उजराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में रजतार पकड़ेगा मानसून

जयपुर, लखनऊ, भोपाल, देहरादून। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बुंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झुंजरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सर्वाई माधोपुर, सीकर, सिरोंही, टोंक, उदयपुर, जालोर, नागौर और पाली में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, उत्तराखंड में क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने अगले 48 घंटों में 'भारी से बहुत भारी बारिश' को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

राजस्थान में बारिश से हुए हादसों में दो की मौत
राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर मंगलवार देर रात तक जारी रहा। सीकर में वर्षा जनित हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। सीकर में मंगलवार शाम से ही हो रही बरसात में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं तो वहीं बरसात के कारण नीमकाथाना इलाके के मावन्डा गांव में मकान ढहने से एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। नीमकाथाना में छात्रावास के एक कुण्ड में पानी भरने से मनीष नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह 8.30 बजे तक जयपुर में 85.4 मिलीमीटर, सीकर में 59.2 मिलीमीटर, पिलानी में 41.2 मिलीमीटर, सर्वाईमाधोपुर में 37.0 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ में 36.5 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 14.0 मिलीमीटर, वनस्थली में 9.4 मिलीमीटर, बुंदी में 5 मिलीमीटर, कोटा में 3.4 मिलीमीटर, अजमेर में 2.1 मिलीमीटर और माउंटआबू में 1.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

जस्टिस सीके प्रसाद से मिले जनसंपर्क आयुक्त



मंगलवार को भोपाल में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस सीके प्रसाद से आयुक्त जनसंपर्क पी. नरहरि और अपर संचालक सुरेश गुप्ता ने सीजन्य भेंट कर मध्यप्रदेश में पत्रकारों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

अमानतुल्लाह को आरोपमुक्त करने के खिलाफ याचिका पर कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2010 के उस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को उनका जवाब मांगा जिसमें उन पर दक्षिण दिल्ली की जारी इकाइयों से बाल श्रमिकों को बचाने से श्रम विभाग के अधिकारियों को रोकने और धमकाने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दिल्ली सरकार, खान और एक अन्य आरोपी को नोटिस जारी करके सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त तक अपना जवाब साबित करने के निर्देश दिए। एनजीओ 'बचपन बचाओ आंदोलन' के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राकेश सेंगर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस पुलका ने अदालत से कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने खान और सैफीउल्लाह सिद्दीकी को आरोपमुक्त करते हुए 'साक्ष्यों और रिकार्डों में मौजूद सामग्री को नजरअंदाज किया जो तथ्यों तथा स्थापित कानून के विरोधाभासी है।' यह मामला यहां बटला हाउस, जामिया नगर से पुलिस तथा एनजीओ द्वारा 15 बाल मजदूरों को बचाने से संबंधित है। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने तीन मई को दोनों आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए पुलिस को खिचाई की थी।

मराठा आरक्षण: मुम्बई तक पहुंची आंच, आज कई जगह बंद का आह्वान

महाराष्ट्र में बवाल, गाड़ी फूंकरीं दो की मौत, कई लोग घायल

औरंगाबाद ■ एजेंसी

मराठा आरक्षण के मामले में हो रही देरी और सोमवार को प्रदर्शन के दौरान नदी में कूदकर एक शख्स की खुदकुशी के विरोध में बुलाए महाराष्ट्र बंद हिंसक होने लगा है। औरंगाबाद में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और उन्होंने ट्रकों में आगजनी की। एक पुलिस कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, वहीं दो पुलिसकर्मी घायल है। इस बीच मंगलवार को दो और युवकों ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध में अपने सिर मुंडवा लिए। बंद का सबसे ज्यादा असर मराठावाड़ा इलाके में दिख रहा है। यहां स्कूल और कॉलेज बंद हैं। औरंगाबाद में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई और प्रदर्शनकारी धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि मराठा आंदोलन उग्र होने की वजह से उस्मानाबाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।



मराठा आरक्षण के विरोध में औरंगाबाद में एक प्रदर्शन।



मृतक के परिवार को मुआवजा देने का वादा

मराठा आरक्षण पर औरंगाबाद के सिल्लोड तहसील स्थित कायगांव टोक में एक युवक काका साहेब दत्तात्रय शिंदे (28) ने गोदावरी में छलांग लगा दी थी। उसकी मौत के बाद मराठा आंदोलन घटनास्थल पर अधिक आक्रामक हो गया। मृतक के परिवार को मुआवजा और भाई को नौकरी देने का वादा प्रशासन ने किया। काका साहेब शिंदे के अंतिम संस्कार में भाग लेने गए शिव सेना सांसद चंद्रकांत खेरे के साथ मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धक्का-मुक्की की। बाद में पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर लगाया जाम

औरंगाबाद से मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन की आग धीरे-धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही है। हिंगोली, मराठवाड़ा, मनमाड, क्षेत्र में मराठा आरक्षण की आग फैल गई। आज मुंबई में बड़ी सड़की मंडी और फल मंडी में बंद का आह्वान किया गया है। मराठा क्रांति समाज ने बुधवार को टाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ में बंद का एलान किया है। इस बंद में स्कूल और कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि मंगलवार को कुछ जगहों मराठा आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। दरअसल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 72 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती में मराठों के लिए 16 फीसदी पद आरक्षित रखने का फैसला किया है लेकिन इससे भी आंदोलन की आग शांत नहीं हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त है। इसके अलावा 2019 में ही राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मराठा आंदोलन फडणवीस सरकार और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका। नई भर्ती की घोषणा से आंदोलन को हवा मिली है।

नफरत मिटाओ कार्यक्रम शुरू किया प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल ने

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आई टी विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में शुरू किए गए नफरत मिटाओ देश बचाओ कार्यक्रम की शुरु आत राजीव चौक मेट्रो गेट नंबर एक से की। इसमें आईटी विभाग के दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके पूर्व संसद में 21 जुलाई को भाजपा के खिलाफ अविास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आदर स्वरूप गले लगाया था। राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन पर आईटी विभाग के कार्यकर्ता हाथों में प्ले कार्ड लेकर खड़े थे जिसपर नफरत मिटाओं देश बचाओ, व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर लगी थी। इस कार्यक्रम के आयोजक अनिरुद्ध शर्मा ने बताया कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य राहुल गांधी के संदेश को आगे ले जाना है जिसमें उन्होंने कहा कि नफरत का मुकाबला हम प्यार से करेंगे। उन्होंने संसद में राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गले लगाने का उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो अपनी विपक्षी पार्टी के नेता को गले लगाकर भाईचारे और सम्मान देने का संदेश दिया है। दूसरी ओर जब से भाजपा की सरकार केन्द्र में आई है तब से प्रायोजित हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

न्याय की गुहार इटली में बसे पिता से बेटी को वापस चाहती है भारतीय मां

मुंबई हाईकोर्ट ने जारी किया येलो नोटिस

मुंबई ■ एजेंसी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इटली के रहनेवाले एक शख्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी रखते हुए उनके द्वारा गोद ली हुई बच्ची की तलाश के लिए येलो नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह शख्स कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बच्ची को अपने साथ ले गया था। बच्ची की कस्टडी को लेकर आरोपी व्यक्ति का पांच वर्षों से ज्यादा समय से अपनी पत्नी (जो कि भारतीय है) के साथ विवाद चल रहा है। बता दें कि महिला को काफी समय पहले उनके पति ने छोड़ दिया था।

हाईकोर्ट ने यह गौर किया कि शख्स बच्ची को वर्ष 2015 में अपने साथ ले गया और तथ्यों को छिपाते हुए जुवेनाइल कोर्ट से इस बात के आदेश प्राप्त किए। बता दें कि गोद ली हुई बच्ची की कस्टडी के लिए उनकी मां ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी लेकिन वर्ष 2013 में इस



याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने बैगैर कुछ भी सुने बच्ची की कस्टडी उसके पिता को दे दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2015 में फैमिली कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए निर्देश दिए कि बच्ची को पिता मां के सुपुर्द करें। आदेश का पालन न होने की वजह से हाईकोर्ट ने सीबीआई (इंटरपोल) को निर्देश दिए कि वह रेड ऑर्डर येलो कॉर्नर नोटिस जारी करें। इस मामले में

बच्ची की मां उसका पता लगाने में जुटी हुई हैं। वह चाहती हैं कि जब तक बच्ची वापस भारत नहीं आ जाती है तब तक कम से कम वह वीडियो चैट के जरिए ही एक-दूसरे से संपर्क में रहें। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश जारी करते हुए कहा है, जरूरी कदम उठाते हुए पिता और बच्चे का पता लगाया जाए और उन्हें वापस लाएं।

गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में शख्स का पता लगा लिया गया था। हालांकि, कोर्ट के आदेश पर इस शख्स ने बच्ची को देने से इनकार कर दिया और कहा था कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। इसी महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने कहा कि यह तो साफ है कि विदेश मंत्रालय ने सारे संभव प्रयास किए कि कम से कम बच्ची से उसकी मां की स्काइप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो जाए। हालांकि, इसपर इटली के अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्रद्धालुओं से भरी बस फंसी

इस बीच महाराष्ट्र बंद की वजह से पंडरपुर में आयोजित 'वारी' (एक धार्मिक यात्रा) में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं से भरी बस पिछली रात से लातुर बस स्टैंड पर फंसी हुई है। बस कंडक्टर ने बताया, 'हमें अपने रिस्क पर आगे जाने के लिए कहा गया है। लोगों ने कहा, 'यहां कोई स्टॉप नहीं है और हमारे पैसे भी नहीं लौटाए जा रहे हैं'।

क्यों उग्र हो गया है मराठा समाज

मुख्यमंत्री के खिलाफ चर्च के सबसे बड़े मराठा समाज में आग सुलग रही है। मराठों का गुस्सा उबाल मार रहा है। 72 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती में मराठों के लिए 16 फीसदी पद आरक्षित रखने का सीएम का फैसला आग को ठंडा करने के बजाय और भड़का रहा है। पुजा करने पंद्रपुर न जाने के मुख्यमंत्री के फैसले पर भी मराठा समाज नाराज है। मराठा समाज की लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला मराठों को अपमानित करने के लिए लिया है।

मराठा आरक्षण के समर्थन में उतरी शिवसेना

फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में भागीदार लेकिन बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही शिवसेना ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने कहा कि मराठा आरक्षण में बहुत देरी हो चुकी है। कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, इसे ध्यान में रखना होगा। शिवसेना मराठा आरक्षण का समर्थन कर रही है। जिन लोगों ने आरक्षण का वादा किया था, उन्हें इस मसले को हल करने के लिए सामने आना चाहिए।

जब हम कठिन कायरे को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं, तो चमत्कार हो सकते हैं -अल्बर्ट गिल्बर्ट

हिंसा और हत्याओं पर राजनीति

हिंसा और हत्याओं पर राजनीति में उबाल है। विपक्षी पार्टियों ने संसद में जिस तरह सरकार पर हमला किया उसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कहीं भी लोग कानून अपने हाथों में ले रहे हैं, तो यह देश के लिए अत्यंत ही खतरनाक संकेत है। किंतु इसे कोई रंग देने की कोशिश उचित नहीं है। गोरक्षण के नाम पर अवश्य एक समुदाय के व्यक्ति की हात्या हुई है। किंतु इसी घटना के साथ राजस्थान में ही एक दलित युवक की भीड़ ने दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम करने के कारण पीट-पीट कर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बच्चा चोरी के नाम पर मारी गई मानसिक रूप से बीमार महिला भी उस समुदाय से नहीं है। हाल में बच्चा चोरी के नाम पर मारे गए लोगों को किसी समुदाय के विरु ढ़ हिंसा नहीं माना जा सकता है। वास्तव में चिंता हमारे समाज के सामूहिक चरित्र पर होनी चाहिए। आखिर, लोग इस तरह हिंसक क्यों हो रहे हैं? दुर्भाग्य से राजनीति इस मूल प्रश्न पर विचार करने को तैयार नहीं है। नेताओं का रवैया केवल इसका राजनीतिक लाभ उठाने का दिख रहा है। यह शर्मानक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्चस्तरीय समिति की जानकारी देते हुए भीड़ की हिंसा के खिलाफयथासंभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, किंतु इससे हम आस्त नहीं हो सकते। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, केंद्र की पूर्व में जारी एडवायजरी, अप्म्राहों से बचने की विज्ञापनों द्वारा सलाहों, आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों आदि के बावजूद यह प्रवृत्ति रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके मूल कारणों की गहराई से छानबीन किए जाने की आवश्यकता है। एक दूसरे को दोषी ठहराकर राजनीतिक रोटियां सेंकें जा सकती हैं, पर यदि हिंसा की यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो कैसी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी इसकी कल्पना से ही सहिरन पैदा होती है। आखिर, ऐसा क्या है कि कोई अप्म्राह उड़ा देता है कि बच्चा चोर हैं, गो तस्कर हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं र्कर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं? हमारा मानना है कि संसद इस पर अलग से बहस करने के लिए समय निकाले तथा राजनीतिक गोलबंदी से परे होकर माननीय सांसद समाधान तलाशने पर विचार करें। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ अन्य दलों के नेताओं तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाया जाए जो हिंसा की रिपोटरे को देखकर सच्चाई की तह तक जाए एवं इसे रोकने के उपाय सुझाए।

धरना - प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन करने वाले, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के अच्छे दिन आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर मंतर और वोट क्लब पर धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने का आदेश दे कर नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय हस्तर न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने वायु प्रदूषण और प्रदर्शनकारियों द्वारा गंदगी फैलाने के बिना पर जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। गैर सरकारी संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन और कुछ अन्य संगठनों ने एनजीटी के इस आदेशको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत का विास है कि क्षेत्र की संवेदनशीलता और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है। इसीलिए जंतर मंतर और वोट क्लब जैसे स्थानों पर धरना-प्रदर्शन करने पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब चुनावों के दौरान राजनीतिक नेता वोट मांगने के लिए जनता के पास जा सकते हैं तो चुनाव बाद जनता उनके प्रति विरोध प्रदर्शन या अपनी लंबित मांगों की पूर्ति पर सरकार ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनके कार्यालयों के पास क्यों नहीं जा सकती? यह सच है कि लोकतंत्र में आम जन को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है। धरना-प्रदर्शन इसका प्रत्यक्ष माध्यम है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुईथी। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा, किसी एक के धरना-प्रदर्शन के अधिकार से दूसरे के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग जंतर मंतर पर एनजीटी के लगाए प्रतिबंध को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। एनजीटी ने पर्यावरण कानून का हवाला देकर यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगाई थी न कि लोगों के मौलिक अधिकारों पर। जंतर मंतर के परदेले रामलीला मैदान दिया गया था। इसलिए अगर धरना-प्रदर्शन से पर्यावरण को वास्तव में क्षति पहुंच कर रही है तो इस और भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सत्संग

प्रकृति

ईसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है। यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे। वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रेत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह, क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कोड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर ईसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे-सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रेत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है।

‘‘नाम में क्या रखा है!’’

कांग्रेस ने इसे भारत का दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। हम इसे भारत में जनतंत्र मात्र की रक्षा की लड़ाई कहना चाहेंगे क्योंकि जनतंत्र अगर रहेगा तो सत्ता पर राजनीति के सभी अलग-अलग प्रतिद्वंद्वी दावेदारों का भी अस्तित्व रहेगा अन्यथा लिंचिंग, हत्याओं की श्रृंखला, जनसंहारों की राजनीति का प्रत्येक संवेदनशील नागरिक तक को शिकार होना होगा। राजेश जोशी की कविता है-‘‘जो निरपराध होंगे, वे मारे जाएंगे।’ भारत की जनता ने अपनी आजादी के बाद के राजनीतिक जीवन में जनतंत्र मात्र की रक्षा की एक ऐसी, भले छोटी ही क्यों न हो, महत्त्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है। इंदिरा गांधी के आंतरिक आपातकाल के खिलाफ लड़ाई-जब इंदिरा गांधी में सर्वग्रासी सत्ता का रुझान दिखाई दिया था और उस समय इंदिरा गांधी को पराजित करके पटरी पर लाने की लड़ाई में किसी ने भी लड़ाई में उतरे लोगों की अपनी-अपनी पहचानों की एक बार के लिए परवाह नहीं की थी। चूंकि सन 1975 से 1977 के उस अनुभव के साथ कांग्रेस दल का नाम जुड़ा हुआ है, संभवत: इसीलिए अभी कांग्रेस कार्यसमिति आने वाले दिनों की इस एक और बेहद चुनौती भरी, जनतंत्र की रक्षा की कठिन लड़ाई को ‘‘दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन’’ बता रही है। लेकिन, सारत: यहां कहना पड़ता है -‘‘ नाम में क्या रखा है !’’ मूल बात, जो कांग्रेस कार्यसमिति ने बिल्कुल सही कही है, वह यह है कि 2019 हरेक भारतवासी के लिए भारत मात्र की अवधारणा की रक्षा की लड़ाई है। इसमें शामिल होने वाले का अपना कोई रंग नहीं होगा, कोई जात, कोई पहचान और कोई विचारधारा नहीं होगी-वह सिर्फ भारत में जनतंत्र की रक्षा का सेनानी होगा।

कांग्रेस ने अंतत: अपनी कार्यसमिति की बैठक में आज की भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सही शिनाख्त कर ली है-यह मोदी पार्टी है। मांब लिंचिंग, गुप्त हत्या, हत्याओं की श्रृंखला और जनसंहार इसकी राजनीति के, सर्वग्रासी सत्ता और पूर्ण वर्चस्व के इसके लक्ष्य के क्रियात्मक रूप हैं। अपनी इसी शिनाख्त के आधार पर कांग्रेस ने यह जरूरी निर्णय लिया है कि 2019 के चुनाव में उसे अपने किसी तथ्याकथित दूरगामी हित की बिना परवाह किए देश के सभी स्तर के अलग-अलग मतावलंबी लोगों को भी एकजुट करके भारत में मोदी पार्टी को पराजित करना है। कांग्रेस ने इसे भारत का दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। हम इसे भारत में जनतंत्र मात्र की रक्षा की लड़ाई कहना चाहेंगे क्योंकि जनतंत्र अगर रहेगा तो सत्ता पर राजनीति के सभी अलग-अलग प्रतिद्वंद्वी दावेदारों का भी अस्तित्व रहेगा अन्यथा लिंचिंग, हत्याओं की श्रृंखला, जनसंहारों की राजनीति का प्रत्येक संवेदनशील नागरिक तक को शिकार होना होगा। राजेश जोशी की कविता है-‘‘जो निरपराध होंगे, वे मारे जाएंगे।’ भारत की जनता ने अपनी आजादी के बाद के राजनीतिक जीवन में जनतंत्र मात्र की रक्षा की एक ऐसी, भले छोटी ही क्यों न हो, महत्त्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है।

इंदिरा गांधी के आंतरिक आपातकाल के खिलाफ लड़ाई-जब इंदिरा गांधी में सर्वग्रासी सत्ता का रुझान दिखाई दिया था और उस समय इंदिरा गांधी को पराजित करके पटरी पर लाने की लड़ाई में किसी ने भी लड़ाई में उतरे लोगों की अपनी-अपनी पहचानों की एक बार के लिए परवाह नहीं की थी। चूंकि सन 1975 से 1977 के उस अनुभव के साथ कांग्रेस दल का नाम जुड़ा हुआ है, संभवत: इसीलिए अभी कांग्रेस कार्यसमिति आने वाले दिनों की इस एक और बेहद चुनौती भरी, जनतंत्र की रक्षा की कठिन लड़ाई को ‘‘दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन’’ बता रही है। लेकिन, सारत: यहां कहना पड़ता है -‘‘ नाम में क्या रखा है !’’ मूल बात, जो कांग्रेस कार्यसमिति ने बिल्कुल सही कही है, वह यह है कि 2019 हरेक भारतवासी के लिए भारत मात्र की अवधारणा की रक्षा की लड़ाई है। इसमें शामिल होने वाले का अपना कोई रंग नहीं होगा, कोई जात, कोई पहचान और कोई विचारधारा नहीं होगी-वह सिर्फ भारत में जनतंत्र की रक्षा का सेनानी होगा।

कांग्रेस कार्यसमिति ने बिल्कुल सही भारत मात्र के अस्तित्व पर खतरे को पहचाना है।बीस जुलाई को लोक सभा में मोदी पार्टी की सरकार के खिलाफतेलुगु देशम पार्टी के अविास प्रस्ताव पर बहस में भी 2019 के सारे मुद्दे सामने आए। बहस में राहुल गांधी ने अपने भाषण के प्रारंभ में ही यह सवाल उठाया कि क्या मोदी सरकार की किसी भी बात का कोई मूल्य रह गया है? मोदी ने किनके इशारों पर नोटबंदी की? क्यों जीएसटी देश के सामान्य व्यापारियों के जी का

चलते चलते

लीजिए अब पुकारता हूं गीत

नीरज जी तैनेँ पहली बार कब देखे ?-जब मैं सात-आठ वर्ष का था, तब अपने मौहल्ला अहीरपाड़ा के घर में उन्हें देखा था। मेरे पिता के अनन्य मित्र थे। मुझे साठ साल पहले ही समझ में आ गया था कि ये कुछ अलग हैं। इनके अंदर कुछ है, जो अपनी ओर खींचता है। समझ अधिक नहीं थी, लेकिन इतनी कम भी नहीं थी। गली के बच्चे हमारे घर में झांकते थे तो मुझे गर्व होता था कि देखा, तुम्हारे घर नहीं, मेरे घर आए हैं। -कोई किस्सा सुना उनको!-सैकड़ों किस्से हैं। इन गुजरें साठ सालों में उनके साथ कितने कवि सम्मेलनों में गया, गिनती नहीं की। सौ से अधिक कवि सम्मेलनों में तो ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने अध्यक्षता की और मैंने संचालन। मैं उन्हें जब काव्य-पाठ के लिए बुलाता था तो कुछ इस तरह,

“लीजिए अब पुकारता हूं गीत-सम्राट को, जिनकी

बानी प्रेम की बानी है, जिनका शब्द-शब्द प्यार की कहानी है। कहानी जो भावनगर से अर्थनगर तक जाती है, हालांकि कई बार अर्थ जगत की तलाश में अलीगढ़ से बंबई जाकर रुक जाती है। लेकिन चूंकि ठाठ फकीरी का है, मामला आसू के सम्मान का है, सरोकार देश के सबसे गरीब ईसान का है, इसलिए

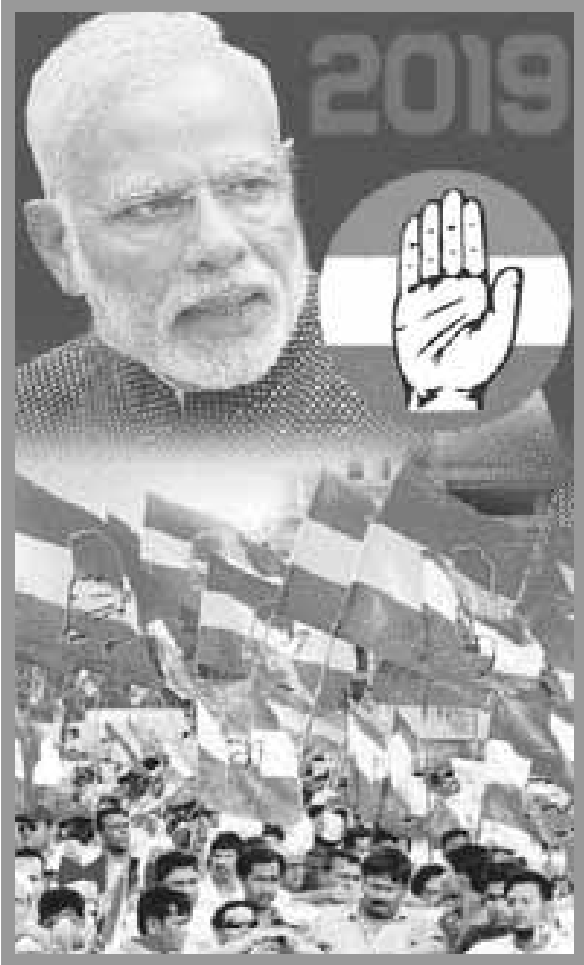
फोटोग्राफी...



रॉयल वेल्श शो...
वेल्स के शहर लेलेनवीड में बुधवार को रॉयल वेल्श शो के दौरान अपने पालतू के साथ आया युवक। वेल्स के सबसे बड़े इस शो में किसान अपने मवेशी लाते हैं। वीरवार तक चलने वाले शो में न सिर्फ वेल्स और ब्रिटेन बल्कि पूरे यूरोप से किसान पहुंचते हैं।

सतीश पेडणोकर

जंजाल बन गया ? राहुल गांधी ने साफ कहा कि भारत का हर आदमी जानता है, नरेन्द्र मोदी किन के हित में काम कर रहे हैं। सबने उन कंपनियों के विज्ञापन देखे हैं, जिन्होंने नोटबंदी के बाद मोदी का स्वागत किया था। अंबानी के जियो के विज्ञापन में मोदी होते हैं। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में अनिल अंबानी को सीधे पैंतालीस हजार करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से सदन में और बाहर भी लगातार असत्य बोलने के लिए बाध्य किया। राहुल गांधी ने अमित शाह के पुत्र का जब नाम लिया, तो सारे भाजपाई सांसद जिस प्रकार खड़े हो गए उससे तो यह लगा कि आगे संसद में माल्या, नीरव मोदी जैसों का भी नामोच्चार निषिद्ध हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा-प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं है, भागीदार हैं। इन्होंने भारत के सबसे बड़े पूंजीपतियों का अढ़ाई लाख करोड़ रु पये माफकिया, लेकिन किसान का मामूली कर्ज भी माफनहीं करेंगे। आज इनके चेहरे पर घबड़ाहट है। ये मेरी से नजर से नजर नहीं मिला सकते हैं। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि मेरे भाषण का वे पंद्रह मिनट भी सामना नहीं कर पाएंगे। बीस जुलाई को वास्तव में भी वही हुआ। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उनके भाषण और उसकी भाषा में काट-छांट की कोशिश की। वह चाहती थीं कि राहुल गांधी अपने भाषण के प्रवाह को रोक कर बीच-बीच में दूसरों को बोलने दें। पूरा शासक पक्ष आपके के बाहर हो गया था । एक बार तो उनके भाषण के बीच में ही सदन को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने महिलाओं की असुरक्षा का सवाल उठाया और लिंचिंग की तरह के जघन्य कृत्यों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को उनके प्रति मौन स्वीकृति कहा। राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी बात कही वह यह थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी



अध्यक्ष अमित शाह हम सबसे दूसरी धातु के लोग हैं। ये सत्ता के बिना जी नहीं सकते। ये जानते हैं कि जिस दिन ये सत्ता खो देंगे, इनके खिलाफदेर सारी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। राहुल गांधी के जवाब में इस दिन नरेन्द्र मोदी खिसियाए लग रहे थे। राहुल गांधी अपने भाषण के अंत में नफ़्त की राजनीति का एक प्रति-आख्यान रचते हुए मोदी से लग मिले थे। मोदी ने राहुल के उस आलिंगन के प्रति खीझ उतारने में ही डेढ़ घंटा समय गंवा दिया। सारे अखबारों ने नोट किया कि मोदी क्या बोले, वह किसी की समझ में नहीं आया, वे राहुल की झप्पी के असर से मुक्ति में ही डूबे रह गए। बहरहाल, 20 जुलाई के बाद से ही 2019 की लड़ाई का बिगुल फुंक गया है। कांग्रेस कार्यसमिति ने भी सभी विपक्षी दलों के सामने इस लड़ाई की दिशा बांध दी है। बाकी दल भी जल्द ही 2019 के बरक्स अपनी रणनीति को तय करने के लिए बैठकें करेंगे। तेलुगु देशम, शिव सेना और टीएमसी जैसे दलों ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफजनता की गोलबंदी का आह्वान करना भी

शुरू कर दिया है। इतना साफहै कि 2019 के चुनाव में मोदी-आरएसएस को परास्त करने के परिप्रेक्ष्य को भूल कर कोई भी चुनावी रणनीति बेकार है। जो पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मोदी-आरएसएस की मदद करेगी, वह वास्तव में अपनी आत्महत्या का नोट लिखेगी। मोदी का सत्ता में लौटना जनतंत्र का अंत और सत्ता में भागीदारी के अन्य सभी दावेदारों का भी अंत होगा। उनको परास्त करने से ही समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारे व समाजवाद के लिए भी संघर्ष का रास्ता प्रशस्त होगा।

प्रबंधन प्राधिकरण मंजूरी

सरकार द्वारा आखिरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद कावेरी को लेकर हो रहा मूर्खतापूर्ण कोलाहल अब शांत हो चुका है। इसलिए अब इस मुद्दे पर ठहर कर विचार करना उचित होगा। इस मुद्दे का इतिहास देखते हुए अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि प्राधिकरण का फैसला आने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा फिर जोर पकड़ेगा क्योंकि दोनों राज्य किसी समझौते के बजाय अपनी अस्मितामूलक राजनीति को बचाए रखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। कावेरी विवाद लगभग एक सदी पुराना है। 1924 में मैसूर और मद्रास में इसको लेकर एक समझौता हुआ जो 50 सालों तक किसी तरह चला। 1974 में 50 साल पूरे हो जाने के काफी सालों बाद 1990 में दोनों राज्यों में नदी के पानी के बंटवारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ट्रिब्यूनल बना। ट्रिब्यूनल के फैसले को कर्नाटक ने नहीं माना और फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश पारित कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों राज्यों में हिंसात्मक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। यह सिलसिला चलता रहा। ट्रिब्यूनल सुनवाई करता रहा, कावेरी नदी प्राधिकरण बना, कावेरी निगरानी समिति बनी। लेकिन यह झगड़ा चलता रहा और कोई मान्य समझौता कभी हो नहीं पाया। इस सबके बीच कावेरी नदी की हालत खराब होती रही। किसी ने इसके महत्त्व का विषय नहीं समझा। आज नदी और इससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र की हालत बदतर हो चुकी है। कर्नाटक में कुर्ग के पहाड़ों से इसका उद्गम होता है। इस पहाड़ी इलाके में 19वीं शताब्दी में कॉफी की खेती शुरू हुई। कॉफी को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सबके बावजूद काफी सालों तक इस इलाके की पारिस्थितिकी काफी हद तक बची रही। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशकों से पारिस्थितिकी बदलती चली गई। निर्यतण बाजार में कॉफी की मांग से इस इलाके में खेती फैलाने के लिए वनों की कटाई शुरू हो गई। एक अध्ययन के अनुसार 1977-1997 के बीच इलाके के वन क्षेत्रों में 28 प्रतिशत गिरावट आई। वन क्षेत्र 2566 वर्ग किमी. से घटकर 1841 वर्ग किमी. रह गया. परिणामस्वरूप वष में कमी आती गई। पिछले 40 सालों के दौरान इलाके में बारिश का मौसम मात्र 14 दिनों का होकर रह गया है। नदी को पानी मिलना कम हो गया। भूजल काफी नीचे चला गया है। नदी के किनारे पानी की खपत करने वाले उद्योग भी शुरू हुए। चीनी मिल और अन्य छोटे-बड़े उद्योगों का कचरा और दूषित पानी नदी में गिराया जाने लगा। मैसूर और आसपास के इलाकों का पानी जहरीला होता जा रहा है। कर्नाटक में अंधाधुंध शहरीकरण ने कावेरी और उसकी सहायक नदियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कावेरी की लगभग सारी सहायक नदियां सीवेज के पानी से गंदी हो चुकी हैं। तमिलनाडु पीड़ित होने का रोना रोते रहता है। खेती, उद्योग, सीवेज, वनों की कमी, कम वष, सूखा, भूजल व पौने के पानी की कमी और उसका दूषित होते जाना, छोटी नदियों का सूखना, कावेरी नदी का जलस्तर घटते जाना। राज्य सरकारों, किसान संगठनों, सिविल सोसाइटी, स्थानीय शहरी विकास निकायों, ग्रामीण निकायों, पर्यावरणविद् और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इस मामले में एक साथ मिलकर स्थायी समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत है। अगर हम नदी और पानी को वाकई बचाना चाहते हैं, तो बचा सकते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों को सोचना होगा कि अगर नदी ही नहीं बची तो पानी कहां से आएगा? वैसे इस दिशा में सोचने की जरूरत तो पूरे देश को है।

उसके थन में बरतलवा होने लगा। उसकातावश गया उसने धन पर हाथ लगाया गया तो दुध निकल आया। फिर ब्या था वह फिर बाफ फिर से पूरे परिवार के लिए चढती कामधेनु बन गई। दोनों समय दो-दो लाठी दुध पाकर परिवार आया खुशी से फूला नहीं समाता। पशु चिकित्सक डा. आखी मौय्य ने बताया कि ट्रीटमेंट के जरिए ऐसा संभव है। जब कोई गाय वर्षाधारण करने लायक हो जाती है और किसी कारणवश बांझ निकल जाती है तो उसका उपचार किया जाता है। वह बगैर बलचा जने दुध देने लगती है। उनके द्वारा भी दुध ऐसे केसों में इकट्ठा किए गए हैं। मगर इस मामले में संभव है कि शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से हार्मोन इसके लिए उत्तरिक का कारण हो।

सचिन विस्तार में बिमारियों को सूड़ा की तरफ से खुला आमंत्रण ? सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वापस ली गई



सूरत। सचिन विस्तार में ऐसा लगता है कि सफाई अभियान के नाम पर कचरा संग्रह किया जा रहा हो इस तरह का तालाब बन गया है जहां एक तरफ सफाई अभियान के नाम पर लोखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं सचिन सुड़ा सेक्टर 3 में खुली जगह में पानी भरने से आसपास के लोग इस तरह गंदगी के ढेर लगा कर रखे हैं। जिससे वहां रहने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं, और डॉक्टर के लिए आमदनी का जरिया बनाया जा रहा है। गंदगी के पास में ही स्कूल होने के बावजूद भी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पानी भरने से पास ही गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई बिल्डिंगों की नींव भी कमजोर होकर गिरने की आशंका वहां रहने वाले लोगों द्वारा जताई गई है। तस्वीरों में दिखाई देता स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर।



अहमदाबाद । सफाई कर्मचारियों के वारिसदारों को नौकरी सहित की विभिन्न १६ पेन्डिंग मांगों को लेकर शहर के १५ हजार सफाई कर्मचारियों ने पिछले तीन दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये। हालांकि बुधवार को म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरा और नौकरीमंडल के पदाधिकारियों के बीच आयोजित हुई समाधानकारी बैठक के अंत में सत्तातंत्र की तरफ से संतोषजनक आश्वासन दिए जाने पर नौकरीमंडल ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वापस लेने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की गई थी। पिछले तीन दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वापस लेने से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन के साथ-साथ शहर के लाखों नागरिकों ने राहत महसूस किया है। नौकरीमंडल के पदाधिकारियों और सफाई कर्मचारियों ने शहर को फिर से स्वच्छ बनाने का उद्देश्य लेकर कार्यरत करने की घोषणा की गई थी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पिछले तीन दिन से चल रही थी। अधिकतर कर्मचारियों ने हड़ताल रखकर मुंडन कराकर अनूठा विरोध दर्ज कराया था। हालांकि गत दिन हड़ताल के दौरान सफाई कर्मचारियों ने मर्यादा पार करके शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों पर गंदा कचरा डालकर गंदगी फैलाने का गंभीर अपराध किया था।

कांग्रेसी महिला पदाधिकारीओं ने आरोपी जयंति भानुशाली को गिरफ्तार करने की मांग की

सूरत: प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशान डिजाइनर पर हुये बलात्कार प्रकरण में भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयंति भानुशाली को तात्कालिक गिरफ्तार किये जाने की मांग की गई और पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए,



युवती मानों आरोपी हो इस तरह पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जबकि कॉर्पोरेटर दिनेश काछड़िया के सीडी कांड में भोग बननेवाली युवती की संलिप्तता होने के संदर्भ में पूछे जाने पर कांग्रेस की अग्रणी और महिला

प्रमुख ने इस संदर्भ में कोमेन्ट करने से मना कर दिया। जबकि भाजपा नेताने ऐसा आक्षेप किया है कि कांग्रेस फायनान्स करके भाजपा को बदनाम कर रही है जिसका कांग्रेस महिला प्रमुख कड़ा जवाब देते हुये कहा कि जयंति भानुशाली के

खिलाफ हुई दुष्कर्म की शिकायत में अब सूरत महिला कांग्रेस मैदान में आ गई हो इस तरह भाजपा नेता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। कांग्रेस की महिलाओं ने आगे कहा कि यदि पन्द्रह दिन के भीतर गिरफ्तार कर योग्य जांच नहीं की जायेगी तो महिलाओं के हित में वे आंदोलन भी करेंगी। साथ ही भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुये कांग्रेसी महिलाओं ने बताया कि स्त्री सशक्तिकरण की बात करनेवाले भाजपा के राज में महिलायें शिकायत करती है तो उनकी शिकायत नहीं ली जाती। जो शर्मजनक बात है।

महिला सुस्त्रा के कड़े कानून होने के बावजूद बलात्कार के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने संसद में

दी जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 से 2016 तक देश में बलात्कार के 1.10 लाख से अधिक मामले दर्ज हुये हैं। जबकि गुजरात में 13754 महिला लापता हुई हैं और उसमें 1887 बलात्कार के मामले दर्ज हुये हैं।

हालांकि सूरत में बलात्कार के आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर उनके पास जवाब नहीं था। कांग्रेस महिला प्रमुख ने महिला पर होने वाले बलात्कार के संदर्भ में कांग्रेस महिलाओं के साथ होने की बात कही। लेकिन सूरत में अब तक महिलाओं पर हुये बलात्कार के एक भी मामले में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता या नेता सामने नहीं आये। अब मामला राजनीतिक होने से कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। अतिरिक्त में महिला प्रमुख

ने कहा कि 15 दिन के भीतर यदि गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे।

सूरत शहर महिला कांग्रेस कमेटी के पास देशभर में हुये बलात्कार के आंकड़ों सहित गुजरात में महिलाओं के लापता होने की जानकारी थी। लेकिन स्वयं अपने शहर में हुये बलात्कार के मामलों की कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा बलात्कार का भोग बनी युवती से कांग्रेस की महिला प्रमुख नहीं मिली और उससे मिलकर जानकारी लिये बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। वास्तव में तो महिला प्रमुख को पहले युवती की आपबीती जाननी चाहिए कि उसके साथ क्या-क्या हुआ? सारी जानकारी लेनी चाहिए थी।



सूरत। डिंडोली कक्वाडा रोड़ पर गटर का ढक्कन टुटने से वहां पर बारिश के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है लेकिन सूड़ा के अधिकारी यहां पर दुर्घटना होने की राह या कुछ और पता नहीं क्योंकि पिछले कई महिनों से टुटे ढक्कन के साथ सड़क में बने इस गड्ढे में गिरने से किसी भी व्यक्ति की जान को आफत हो सकती है।

सूदखोरी के मामले में गुजराती डिरेक्टर को शिकार बनाया गया
अहमदाबाद । गुजरात में गरीब किसानों के बाद सूदखोर के आतंक से बड़ौदा में एक गुजराती फिल्म डिरेक्टर को शिकार बनाया गया है। बड़ौदा शहर में गुजराती फिल्म स्माइल कीलर के डिरेक्टर ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने से भारी सनसनी मच गई है। विशेष करके गुजराती फिल्म उद्योग में इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। गुजराती फिल्म डिरेक्टर हितेश परमार ने सूदखोर के आतंक से परेशान होकर आत्महत्या किया हो यह जानकारी सामने आने पर सूदखोर के मामले पर चर्चा ज्यादा होने लगी है। सूदखोर के आतंक से आत्महत्या करने की चिड़्ही मिलने पर पुलिस ने इसके आधार पर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है।



नदी में फेके पुत्र का मृतदेह विकृत हालत में 10 दिन बाद मिला

सूरत: बारडोली वणेसा गांव के निशित ने सगे पुत्र को नदी में फेक दिया था। इस घटना में 10 दिन तक पुलिस और फायरब्रिगेड द्वारा जांच की गई। ऐसे में 10वें दिन मरोली समीप मीढोडा नदी में पानी का स्तर कम होने से बालक नीव का मृतदेह विकृत हालत में मिला। जिसका पुलिस ने कब्जा लेकर आगे की जांच कार्यवाही शुरू की है।

नौव प्रकरण में पिता निशित पुलिस के समक्ष वारंवार निवेदन बल रहे होने से ऐसी भी आशंका चल रही थी कि उसने बालक को नदी में फेका ही नहीं होगा हालांकि मृतदेह मिलने से तमाम आशंकाओं का अंत आ गया है। निशित के पास से तीन बार पुलिस ने घटना का रिकन्स्ट्रक्शन भी कराया था। फायर ब्रिगेड द्वारा मीढोडा नदी के आसपास के खेत से लेकर दरिया तक जांच की गई। जिसमें अंत में मरोली समीप मीढोडा नदी किनारे रेलवे ब्रिज समीप से मासूम बालक नीव का विकृत हालत में मृतदेह मिला।

पिछले दस दिन से बारडोली में नीव की चर्चा चल रही है। आरोपी निशित नीव को नदी में फेक देने की बात पर अडग था। जिससे पुलिस भी नीव को खोजने के लिए मीढोडा नदी में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ खोज कर रही थी। जिसमें नीव की खोजबिन कर रही टीम दरिया के समीप पहुंच गई थी। जिस दिन नीव को नदी में फेका गया था उस दिन फिलहाल की अपेक्षा नदी का स्तर 10 से 12 फुट अधिक था और इस दौरान नदी के पानी किनारे स्थित गन्ने के खेत और अन्य फसलों के खेत में भी पानी घूस गया था। जिससे नीव सुरनिश्चित किस दिशा में गया होगा यह जाना नहीं जा सका था। जिससे टीम ने आसपास के खेत में जाकर भी जांच की थी। हलांकि नीव का पता चलने से फायर ब्रिगेड की कार्यवाही प्रशंसनीय कही जायेगी।

दो वर्ष की सजा बाद हार्दिक आक्रामक मूड में दिखे अब आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी : हार्दिक

अहमदाबाद । विसनगर कोर्ट ने तोड़फोड़ और हिंसा केस में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराकर दो वर्ष की सजा बुधवार को सुनायी गई। हालांकि इसे जमानत भी दिया गया। जमानत मिलने के बाद हार्दिक पटेल ने मीडिया के साथ बातचीत करके भाजपा सरकार पर फिर से निशाना साधा है। हार्दिक ने यह कहा है कि, २५ अगस्त को अनिश्चितकालीन उपवास पर जाने की उनकी योजना कायम है। यह उपवास ऐतिहासिक बनेगा। बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। हार्दिक ने यह भी कहा है कि, सरकार के विरुद्ध उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हार्दिक ने यह कहा है कि, सरकार अंग्रेज बनेगी तो उनको भगतसिंह बनने में आपत्ति नहीं है। चुनाव के संदर्भ में कहा है कि, जरूरत होगी तो चुनाव भी लड़ेगा। उपवास के लिए अहमदाबाद में मंजूरी मांगी गई है। हार्दिक ने कहा है कि, सत्तापक्ष भाजपा यह मानता हो

कि, हार्दिक को जेल में भेजना है लेकिन हार्दिक आंदोलन शुरू किया तब से लड़ाई के इरादे के साथ मैदान में उतरे है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक ने कहा है कि, भाजपा सच्चाई किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लड़ाई चलाने से इसे रोक नहीं सकेगा। विसनगर कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी। फैसले के बाद हार्दिक ने कहा है कि, सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आरपार की लड़ाई लड़ने की हार्दिक ने बात की थी। हार्दिक ने यह भी कहा है कि, सरकार को जो करना है वो करे। जो सजा दी है इसके डरते नहीं है। न्याय के लिए ऊपरी कोर्ट में जायेंगे। सजा का डर बताने से वह नहीं डरेंगे। अंतिम आरपार की लड़ाई में न्याय अब लेने का प्रयास किया जाएगा। यह लड़ाई व्यक्ति की नहीं है विचार के साथ की लड़ाई है। हार्दिक ने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी

बतायी है। कई पेशकश कोर्ट में की थी लेकिन जनतंत्र की हत्या की जा रही हो ऐसा दिखाई दे रहा है। शिकायत में हार्दिक पटेल, विसनगर का उल्लेख है। जांच में इस अनुसार हुआ है। मैं और लालजी कार्यक्रम पूरा करके निकल गये थे। घटना बाद में होने का उल्लेख है फिर भी स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। अनिश्चितकालीन उपवास का कार्यक्रम कायम रहेगा। घर बैठे रहे यह उनके स्वभाव में नहीं है।

कर्णावती क्लब से एयरपोर्ट तक शटल सर्विस घाटे में

अहमदाबाद । अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए गत दिसम्बर, २०१७ से शहर के एसजी हाईवे पर स्थित कर्णावती क्लब से एयरपोर्ट तक शटल सर्विस घाटा का साबित हुआ है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन के सार्वजनिक परिवहन सेवा की एएमटीएस और बीआरटीएस यह दोनों संस्था घाटे में चली गई यह प्रकार की शटल सर्विस से आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर भी एयरपोर्ट को कनेक्ट करती यह शटल सर्विस का यात्री लाभ लेते है फिर भी कुछ कारणों से इसे चलायी जा रही है। इतना ही नहीं एयरपोर्ट की यह शटल बस को कर्णावती क्लब से

एयरपोर्ट तक स्थायी स्तर पर चलाने की दरखास्त रखी गई है, जिसकी वजह से एक नया विवाद पैदा हो गया है। गत २१ दिसम्बर, २०१७ से रूट नंबर १००० कर्णावती क्लब से एयरपोर्ट वाया इस्क्रेन, नेहरूनगर, गुजरात कॉलेज, नटराज सिनेमा, इन्कमटैक्स, वाडज, सुभाषब्रिज सर्कल, शाहीबाग, अंडरब्रिज, केम्प हनुमानजी शटल सर्विस को वास्तव में तो तीन महीने के प्रायोगिक स्तर पर चलाने की प्रारंभिक मंजूरी दी गई थी। यह शटल सर्विस में कुल छह बस रूट में रखी गई है और यह सभी छह बस के दिनभर के कुल सिर्फ ४५० से ५०० पैसेन्जर होने के बावजूद भी प्रशासन को औसत आय सिर्फ १५ हजार रुपये की होती है।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्स नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।